Dr.Raman Kumar Thakur

Asstt.prof. (Guest) Deptt.of Economics, D.B.College, Jaynagar.

Class:-B.A.Part-2(Hons)

Date:-23-07-2020.

Topic:- 1991 की वर्तमान औद्योगिक नीति (Present Industrial policy of 1991) जून, 1991 मैं नरसिंह राव सरकार द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद देश में आर्थिक नीतियों मैं बड़े पैमाने पर परिवर्तन करते हुए 24 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की. इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया. बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया. वर्तमान में लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या घटकर 5 रह गई है। नई औद्योगिक नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई है. तथा विभिन्न उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को सरल बना दिया गया है। वर्तमान औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 से लागू है इसका प्रतिपादन दो चरणों में किया गया एक तो 24 जुलाई 1991 को जिसका संबंध बड़े एवं मध्यम उद्योगों से है। और दूसरा 6 अगस्त, 1991 को जो लघु उद्योग से संबंधित है। यह दोनो हीं औद्योगिक नीति अब तक की सभी नीतियों से हटकर है। इसलिए इसे खुली, उदार एवं क्रांतिकारी नीति कहा गया है.इस नीति में मुख्य रूप से विदेशी सहयोग बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना. सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा की योग बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं निरंतरता के साथ परिवर्तन आदि पर विशेष बल दिया गया. इस नीति से निजी क्षेत्र को काफी सीमा तक उन्मुक्त होकर कार्य करने का अवसर मिलेगा और वह अपने आप को प्रतिस्पर्धा की योग साबित कर सकेगा.

*** नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य(Objectives of new industrial policy): - नई औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:-**

1). अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना.

2) विदेशी सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ावा देना

3) पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना ।

4) निजी क्षेत्र को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना.

5) आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का विकास करना.

6) उत्पादन क्षमता में विस्तार को बढ़ावा देना.

7) निर्यात बढ़ाने के लिए आयातो उदार बनाना.

*** नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है:-(Main Contents or features of new industrial policy):-**

* **सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति(policy for public sector)- नवीन औद्योगिक नीति विवरण में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:-**

1) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उपकरणों में कमी- उदारीकरण की नीति अपनाने के क्रम में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी की है । 1991 में इनकी संख्या 18 से घटकर 8 कर दी गई है. जिसे 1993 में पुण: घटाकर 6 कर दिया गया है। बाद में यह संख्या घटाकर 3 कर दी गई है। इनमें सुरक्षा सामग्री, रेल ,परिवहन, एवं आणविक उर्जा ,आदेश 1953 की अनुसूची में शामिल खनिज पदार्थ सम्मिलित है ।

2) सहमति समझौतों से काम-काज में सुधार :- इस नीति में यह कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज में सुधार लाने के लिए सहमति समझौतो पर अधिक बल दिया जाएगा तथा उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकार की ओर से इन समझौतों में भाग लेने वाले पक्षों का तकनीकी स्तर भी ऊंचा उठाया जाएगा।